THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (d) The question of integration of Indian Airlines and Air India is still under consideraton.

Mehrotra Committee's recommendations

*42. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:
SHRI KAILASH PATI MISHRA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the recommendations of the Mehrotra Committee which Government have accepted, rejected or modified;

(b) what has been the teachers' reaction thereto; and

(c) since when the Government decision thereon will come into force?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) A statement is laid on the Table of the House. [See Appendix CXLIII, Annexure No. 25].

(b) The decisions of the Government on the scales of pay have generally been welcomed by teachers. However, some Associations of teachers have expressed disatisfaction against the increase in the number of grades and the discontinuance of promotion to the posts of Readers and Professors. Teachers' organisations have also been demanding that the Central Government meets entire expenditure on revision of pay scales instead of 80 per cent.

(c) The revision of scales of pay are effective from 1-1-1986.

राज्यों द्वारा नयी शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

*43. डा० रत्नाकर पाण्डेय :
श्री महेन्द्र प्रसाद :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू शिक्षा सत्र से विभिन्न राज्यों में नयी शिक्षा नीति को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (रा० शि० नी०) में यह परिकल्पना की गई है कि नीति को केन्द्र तथा राज्यों के बीच सहयोगी प्रयासों से कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें अध्यापकों के साथ समाज को पूरी तरह से शामिल किया जायेगा। प्रधान मंत्री ने 30-7-1986 को राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों और संघ शासित क्षेत्रों के उप-राज्यपालों/प्रशासकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को समन्वित करने तथा मानीटर करने के लिए मंत्रिमण्डल तथा सरकारी स्तरों की समितियां गठित करने के लिए लिखा था। तत्पश्चात योजनाओं परियोजनाओं को तैयार करने तथा उसके संबंध में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। नीति कार्यान्वयन के सम्बन्ध में फरवरी और अप्रैल 1987 में नई दिल्ली में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गयी है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (के० शि० स० बो०) ने भी 25-26 जन, 1987 को नई दिल्ली में नीति कार्यान्वयन की समीक्षा की। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अगस्त, 1986 में संसद द्वारा अनुमोदित कार्रवाई-योजना को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) **उच्च अधिकार-प्राप्त समितियां** : लगभग सभी राज्य सरकारों तथा संघ